



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1947 (श10)

(सं० पटना 1024) पटना, मंगलवार, 3 जून 2025

सं० 2/सी0-1010/2009-सा0प्र0-18321  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

15 नवम्बर 2024

श्री अशोक कुमार तिवारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1032/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के विरुद्ध अररिया जिले के अन्तर्गत इंदिरा आवास की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं जमा कराकर डेहटी पैक्स में जमा कर इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के विपरीत कार्य करने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, इंदिरा आवास मद की राशि का दुरुपयोग, गबन तथा कदाचार का मार्ग प्रशस्त करने तथा इंदिरा आवास के लाभार्थियों के चयन में भारी अनियमितता बरतने इत्यादि प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री तिवारी को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 353 दिनांक 29.01.2009 द्वारा निलंबित किया गया था। तत्पश्चात उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9056 दिनांक 09.09.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 12959/2010 (अशोक कुमार तिवारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 19.08.2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री तिवारी को निलंबन से मुक्त किया गया। साथ ही श्री तिवारी के निलंबन अवधि के विनियमन एवं वेतनादि के संबंध में उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवं फौजदारी मुकदमे के फलाफल के आलोक में निर्णय लिये जाने का आदेश संसूचित किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक 3338 दिनांक 26.11.2009 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि जाँच प्रतिवेदन में सभी तथ्यों तथा साक्ष्यों को विचारित नहीं किया गया तथा इस मामले की पूर्ण जाँच नहीं हो सकी थी। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के आदेशानुसार इस मामले की अग्रेतर जाँच की आवश्यकता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(1) के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पुनः विस्तृत जाँच हेतु संशोधित आरोप-पत्र गठित कर साक्ष्य के साथ संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए पुनः अग्रेतर जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक 8389 दिनांक 26.08.2010 द्वारा श्री तिवारी के विरुद्ध गठित पूरक/संशोधित आरोपों पर स्पष्टीकरण की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन, जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य तथा ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पूरक आरोप-पत्र के साथ साक्ष्य अभिलेख आदि को विभागीय पत्रांक 35 दिनांक 03.01.2011 द्वारा आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को भेजते हुए अग्रेतर जाँच कर तीन माह के अन्दर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा अग्रेतर जाँच के उपरान्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध "सेवा से बर्खास्तगी एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं" का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड पर श्री तिवारी से अभ्यावेदन की मांग किये जाने पर उनके द्वारा ससमय अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया।

विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग किये जाने पर आयोग द्वारा विनिश्चित दंड पर सहमति संसूचित की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त श्री तिवारी की सेवा से बर्खास्तगी एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का दंड दिये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति दी गयी।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2977 दिनांक 24.02.2012 द्वारा श्री तिवारी के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी एवं निलंबन अवधि में जीवन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का दंड संसूचित किया गया।

सेवा से बर्खास्तगी संबंधी आदेश के विरुद्ध श्री तिवारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 7586/2013 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2016 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"I find that the case of the petitioner is at least on similar footing to that of Shamim Akhtar, Surendra Roy and Gayanand Yadav, whose dismissal have already been set aside. In the result, the writ petition succeeds. The impugned order of dismissal is set aside in terms of order dated 20.5.2016, passed in C.W.J.C. Nos. 14595 of 2012 and C.W.J.C. No. 20812 of 2012, with the liberty mentioned therein."

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 7586/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 2377/2016 दायर किया गया।

इस बीच सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 7586/2013 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु श्री तिवारी द्वारा एम0जे0सी0 संख्या 1303/2017 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम0जे0सी0 संख्या 1303/2017 में दिनांक 07.11.2017 को पारित आदेश निम्नवत् है :-

"Heard learned counsel for the petitioner and the learned Additional Advocate General No.3 appearing on behalf of the State.

A show cause has been filed today stating that an L.P.A. has been preferred against the order, which is the subject-matter of the present contempt application.

Learned counsel for the petitioner submits that till date, the matter is pending as defective and no stay order has been passed. Therefore, the contempt application may proceed as similarly situated persons have been extended the relief as sought for by the present petitioner.

List this case after two weeks, during which period the learned counsel for the State may take appropriate steps, failing which this Court shall proceed to pass further order in the contempt application."

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 7586/2013 एवं एम0जे0सी0 संख्या 1303/2017 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2977 दिनांक 24.02.2012 द्वारा श्री तिवारी के विरुद्ध अधिरोपित दंड को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15923 दिनांक 13.12.2017 द्वारा निरस्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत सेवा में इस शर्त के साथ पुनः स्थापित किया गया कि विचाराधीन एल0पी0ए0 संख्या 2377/2016 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के फलाफल से आच्छादित होगा।

विचाराधीन एल0पी0ए0 सं0 2377/2016 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"The aforesaid cited decisions of the learned Single Judge has no application to the case in hand for the reasons that it is not common proceedings or joint inquiry so as to take note of decisions reported in CWJC No. 14595 of 2012 and CWJC No. 20812 of 2012. In other words, independently the matter of the respondent is required to be decided by

the learned Single Judge. Accordingly, the State-appellant has made out a prima facie case to the extent that order of the learned Single Judge is not a reasoned order. Hence, order of the learned Single Judge dated 15.07.2016 passed in CWJC No. 7586 of 2013 stands set aside. CWJC No. 7586 of 2013 stands restored on the file of the learned Single Judge. CWJC No. 7586 of 2013 is of the year 2013 and dismissal order is dated 24.02.2012, therefore, the learned Single Judge is requested to decide CWJC No. 7586 of 2013 within a period of four months.

**In the result, the present Letters Patent Appeal stands allowed."**

माननीय न्यायालय द्वारा एल०पी०ए० सं० 2377/2016 में सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 7586/2013 में दिनांक 15.07.2016 को विद्वान एकल जज द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया एवं सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 7586/2013 को पुनः स्थापित किया गया। साथ ही विद्वान एकल जज को चार माह के भीतर सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 7586/2013 में निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री तिवारी को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15923 दिनांक 13.12.2017 द्वारा सेवा में इस शर्त के साथ पुनः स्थापित किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एल०पी०ए० सं० 2377/2016 में पारित किये जाने वाले आदेश के फलाफल से आच्छादित होगा। एल०पी०ए० सं० 2377/2016 में पारित आदेश द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 7586/2013 में विद्वान एकल जज द्वारा दिनांक 15.07.2016 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद् का श्री तिवारी को सेवा से बर्खास्तगी संबंधी आदेश पुनः प्रभावी हो जाता है। समीक्षोपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं पूर्व में मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4137 दिनांक 01.03.2023 द्वारा श्री तिवारी को पुनः सेवा से बर्खास्त किया गया।

बर्खास्तगी की अवधि में श्री तिवारी दिनांक 31.03.2023 को सेवानिवृत्त हो गये हैं।

उक्त एल०पी०ए० सं० 2377/2016 में पारित आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 7586/2013 की पुनः सुनवाई की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2023 को पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है :-

**"13. Having regard to the facts and circumstances of the case, the order of punishment dated 24.02.2012 as also the inquiry report dated 30.03.2011 stand quashed and it is held that the petitioner would be entitled to full back wages along with other admissible consequential benefits.**

**14. The writ petition stands allowed."**

उक्त पारित आदेश के विरुद्ध सरकार द्वारा एल०पी०ए० सं० 1302/2023 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अशोक कुमार तिवारी) दायर की गई है, जो माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु लंबित है।

इस बीच श्री तिवारी द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 7586/2013 में दिनांक 05.09.2023 को पारित आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु माननीय न्यायालय में एम०जे०सी० सं० 1186/2024 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

**"The learned counsel for the opposite parties seeks and is granted six weeks' time for filing show cause showing compliance of the judgment of this Court dated 05.09.2023 passed in CWJC No. 7586 of 2013.**

**Accordingly, list this case after eight weeks."**

उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 7586/2013 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री अशोक कुमार तिवारी से संबंधित सदृश्य मामलों यथा-श्री गयानन्द यादव, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया, श्री सुरेन्द्र राय, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया एवं मो० शमीम अख्तर, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के विरुद्ध बर्खास्तगी का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सम्यक् विचारोपरान्त वापस लेते हुए उन्हें निलंबन एवं बर्खास्तगी की अवधि के देय वेतनादि का भुगतान स्वीकृत किया गया है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि श्री तिवारी दिनांक 29.01.2009 से 25.09.2010 तक निलंबित रहे। श्री तिवारी को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2977 दिनांक 24.02.2012 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15923 दिनांक 13.12.2017 द्वारा सेवा में पुनः स्थापित किया गया। साथ ही श्री तिवारी को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4137 दिनांक 01.03.2023 द्वारा सेवा से पुनः बर्खास्त किया गया।

वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 7586/2013 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अन्य सदृश्य मामलों में लिए गए निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए श्री तिवारी को निलंबन अवधि का पूर्ण वेतनादि का भुगतान करने एवं इनके विरुद्ध विभागीय

संकल्प ज्ञापांक 4137 दिनांक 01.03.2023 द्वारा अधिरोपित पुनः बर्खास्तगी के दंड को निरस्त करते हुए सेवा में पुनःस्थापित करने तथा बर्खास्तगी अवधि (दिनांक 24.02.2012 से 12.12.2017 तक) एवं पुनः बर्खास्तगी अवधि (दिनांक 01.03.2023 से 31.03.2023 तक) का देय पूर्ण बकाया वेतनादि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि श्री तिवारी के संबंध में लिए गए उक्त निर्णय लंबित एल0पी0ए0 संख्या 1302/2023 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम् अशोक कुमार तिवारी) के फलाफल से अच्छादित होगा।

अतएव उक्त निर्णय के आलोक में श्री अशोक कुमार तिवारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1032/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के संबंध में निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

(i) विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4137 दिनांक 01.03.2023 द्वारा अधिरोपित पुनः बर्खास्तगी के दंड को निरस्त करते हुए सेवा में पुनःस्थापित (दिनांक 01.03.2023 से 31.03.2023 तक) किया जाता है।

(ii) निलंबन अवधि (दिनांक 29.01.2009 से 25.09.2010) का पूर्ण वेतनादि भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

(iii) बर्खास्तगी अवधि (दिनांक 24.02.2012 से 12.12.2017) तथा पुनः बर्खास्तगी अवधि (दिनांक 01.03.2023 से 31.03.2023) का देय पूर्ण बकाया वेतनादि की स्वीकृति दी जाती है।

(iv) श्री तिवारी के संबंध में लिए गए उक्त निर्णय लंबित एल0पी0ए0 संख्या 1302/2023 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम् अशोक कुमार तिवारी) के फलाफल से अच्छादित होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1024-571+10-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>